

27 SEPTEMBER 2026

UPSC CSE 2027/28

Weekly Current Affairs

— MCQ's —

SUNDAY SPECIAL

by Dr. Faiyaz Sir

Result Mitra



Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. "राजनीतिक दल" (Political party) शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में तीन स्थानों पर मिलता है।
2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग के पास किया जाता है।
3. निर्वाचन आयोग के पास ऐसे किसी पंजीकृत राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द (Deregister) करने की वैधानिक शक्ति है, जिसने लगातार छह वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ा है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई भी नहीं

उत्तर: (a) केवल एक (केवल कथन 2 सही है)

व्याख्या :

- **कथन 1 गलत है:** मूल संविधान में "राजनीतिक दल" शब्द का कोई उल्लेख नहीं था। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) को जोड़ा गया, जिसमें पहली बार आधिकारिक तौर पर "राजनीतिक दल" शब्द का उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 75(1B) और अनुच्छेद 164(1B) जोड़े गए, जो राजनीतिक दलों से जुड़े सदस्यों की अयोग्यता की बात करते हैं। संविधान में तीन अलग-अलग स्थानों पर इस शब्द का व्यापक उल्लेख नहीं है।
 - **कथन 2 सही है:** भारत में किसी भी नए संघ या संगठन को एक राजनीतिक दल के रूप में काम करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 29A के तहत भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) के पास अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है।
 - **कथन 3 गलत है:** वर्तमान में, भारत के निर्वाचन आयोग के पास किसी पंजीकृत राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने (Deregister करने) की कोई व्यापक वैधानिक शक्ति (Statutory Power) नहीं है, भले ही उस दल ने लगातार छह वर्षों या उससे अधिक समय तक चुनाव न लड़ा हो। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले (इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, 2002) के अनुसार, निर्वाचन आयोग केवल तीन अत्यंत विशिष्ट स्थितियों में ही किसी दल का पंजीकरण रद्द कर सकता है:
 1. यदि दल ने धोखाधड़ी या जालसाजी के जरिए पंजीकरण प्राप्त किया हो।
 2. यदि दल को केंद्र सरकार द्वारा गैर-कानूनी घोषित (प्रतिबंधित) कर दिया गया हो।
 3. यदि कोई दल स्वयं आंतरिक रूप से अपने संविधान में संशोधन कर यह घोषणा करे कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखता है।
- (नोट: चुनाव न लड़ने के आधार पर आयोग दल को 'निष्क्रिय या गैर-मान्यता प्राप्त' तो घोषित कर सकता है, लेकिन उसका पंजीकरण पूरी तरह रद्द नहीं कर सकता। आयोग लंबे समय से सरकार से यह शक्ति देने की मांग कर रहा है।)
- चूंकि केवल कथन 2 सही है, इसलिए विकल्प (a) इसका सही उत्तर है।

Q2. भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत अभियुक्तों (Accused) की पहचान और विधिक सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) के तहत, न्यायालय द्वारा घोषित अपराधियों के खिलाफ उद्धोषणा प्रकाशित करने और उनकी तस्वीरें संलग्न करने का स्पष्ट प्रावधान है, परंतु यह केवल वारंट विफल होने के बाद लागू होता है।
2. 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023' (DPDP Act, 2023) अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए डेटा प्रोसेसिंग को छूट प्रदान करता है, जिसके कारण यह पुलिस द्वारा अभियुक्तों की तस्वीरें जारी करने के खिलाफ कोई वास्तविक सुरक्षा नहीं देता है।
3. 'प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (1980)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अभियुक्तों को हथकड़ी लगाने से संबंधित है, जो विचारणा से पूर्व अभियुक्तों की गरिमा और अनुच्छेद 21 के संरक्षण से सीधे जुड़ता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (A) केवल 1 और 2 | (B) केवल 2 और 3 |
| (C) केवल 1 और 3 | (D) 1, 2 और 3 |

उत्तर: (D) 1, 2 और 3 (तीनों कथन सही हैं)

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 84 (जो पूर्ववर्ती CrPC की धारा 82 के समतुल्य है) के तहत यदि कोई व्यक्ति वारंट जारी होने के बाद भी फरार रहता है, तो न्यायालय उसे घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) घोषित कर सकता है। इस प्रक्रिया में सार्वजनिक उद्घोषणा प्रकाशित की जाती है और व्यावहारिक रूप से उसकी तस्वीर भी लगाई जाती है। लेकिन संपादकीय स्पष्ट करता है कि यह प्रक्रिया केवल वारंट विफल होने के बाद के चरण (Post-Warrant Stage) में लागू होती है, न कि प्रारंभिक जांच या गिरफ्तारी के तुरंत बाद।
- **कथन 2 सही है:** यद्यपि 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023' (DPDP Act) नागरिकों के डिजिटल डेटा की गोपनीयता की रक्षा करता है, लेकिन इस कानून में एक महत्वपूर्ण अपवाद (Exemption) शामिल है। अपराधों की रोकथाम, जांच और अभियोजन (Prevention & Investigation of Offences) के लिए राज्य की एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले डेटा प्रोसेसिंग को इसके दायरे से छूट दी गई है। इसलिए, यह कानून पुलिस द्वारा अभियुक्तों के डिजिटल डेटा या तस्वीरें मीडिया में लीक करने के खिलाफ अभियुक्त को कोई सुरक्षा कवच प्रदान नहीं करता है।

- **कथन 3 सही है:** प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि बिना किसी ठोस सुरक्षा कारण के अभियुक्तों को नियमित रूप से हथकड़ी लगाना (Routine Handcuffing) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनकी मानवीय गरिमा का उल्लंघन है। यह निर्णय आज के डिजिटल युग में बेहद प्रासंगिक है क्योंकि पुलिस द्वारा अभियुक्तों को हथकड़ी लगाए हुए और हाथों में तख्तियां (Placards) थमाए हुए तस्वीरें खींचकर मीडिया में वायरल करना एक प्रकार का "संस्थागत अपमान" और गरिमा का हनन है।

अतिरिक्त बिंदु :

- **BNSS की धारा 43(3):** नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43(3) के अनुसार हथकड़ी लगाने की अनुमति केवल विशिष्ट और गंभीर श्रेणियों के अपराधियों (जैसे आदतन अपराधी, जेल से भागने वाले, या गंभीर व हिंसक अपराधों के आरोपी) के लिए ही दी गई है।
- **प्रेस की स्वतंत्रता बनाम निष्पक्ष सुनवाई:** इस विमर्श का मुख्य केंद्र बिंदु अनुच्छेद 19(1)(a) (प्रेस की स्वतंत्रता और जनता का जानने का अधिकार) तथा अनुच्छेद 21 (अभियुक्त की गरिमा, निजता और निष्पक्ष सुनवाई/Fair Trial का अधिकार) के बीच संतुलन स्थापित करना है।

Q3. भारत के 'राष्ट्रीय गीत' (National Song) और 'राष्ट्रीय गान' (National Anthem) से जुड़े हालिया घटनाक्रमों और विधिक आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026' के तहत मूल अधिनियम (1971) की धारा 3 के दंडात्मक प्रावधानों का विस्तार अब राष्ट्रीय गान के साथ-साथ राष्ट्रीय गीत पर भी कर दिया गया है।
2. भारतीय संविधान में आधिकारिक तौर पर 'राष्ट्रीय गीत' शब्द और वंदे मातरम के छहों अंतरा (Stanzas) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक 'बिजोय इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986)' मामले के निर्णय के अनुसार, किसी भी नागरिक को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और आदरपूर्वक मौन खड़े रहना कोई अपराध नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (A) केवल 1 और 2 | (B) केवल 2 और 3 |
| (C) केवल 1 और 3 | (D) 1, 2 और 3 |

उत्तर: (C) केवल 1 और 3

व्याख्या :

- **कथन 1 सही है:** संसद ने 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026' (Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2026) पारित किया है। यह संशोधन 1971 के मूल अधिनियम की धारा 3 के दायरे को बढ़ाता है। मूल रूप से धारा 3 केवल राष्ट्रगान (Jana Gana Mana) को जानबूझकर गाने से रोकने या बाधा पहुँचाने पर सजा का प्रावधान करती थी, लेकिन अब इस संशोधन के माध्यम से इसे राष्ट्रीय गीत (National Song) पर भी लागू कर दिया गया है।
- **कथन 2 गलत है:** भारतीय संविधान में 'राष्ट्रीय गीत' (National Song) शब्द का कोई संवैधानिक या स्पष्ट उल्लेख नहीं है। 24 जनवरी 1950 को जब 'जन गण मन' को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, तब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक बयान में कहा था कि वंदे मातरम को भी "समान रूप से सम्मानित" किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित 'वंदे मातरम' के केवल पहले दो अंतरा (Stanzas) को ही राष्ट्रीय सभाओं में गाने का ऐतिहासिक समझौता (1937 में कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा) हुआ था, क्योंकि बाद के अंतराओं में मातृभूमि का आह्वान हिंदू देवी-देवताओं के रूप में है। अतः छहों अंतराओं का संविधान में उल्लेख होने की बात पूरी तरह गलत है।

- **कथन 3 सही है:** सर्वोच्च न्यायालय ने बिजोय इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) के प्रसिद्ध मामले (यहोवा के साक्षी/Jehovah's Witnesses संप्रदाय से संबंधित) में माना था कि भारत का कोई भी कानून किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान बजने के दौरान उसके सम्मान में आदरपूर्वक मौन खड़ा रहता है, तो वह कोई अपराध या अपमान नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बिना किसी वैधानिक कानून के केवल कार्यकारी आदेश (Executive Instructions) नागरिकों के मौलिक अधिकारों (जैसे अंतःकरण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) को कम नहीं कर सकते।
- **वर्तमान विवाद:** गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा वर्ष 2026 में जारी सर्कुलर में वंदे मातरम के सभी छह अंतराओं को अनिवार्य रूप से सामूहिक रूप से गाने और इसे राष्ट्रगान से पहले रखने के आदेश दिए गए थे। इसके खिलाफ प्रसिद्ध संगीतकार/कलाकार टी.एम. कृष्णा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
- **न्यायालय का रुख:** न्यायालय ने हालिया टिप्पणियों में दोहराया है कि सरकार यह तय कर सकती है कि राष्ट्रीय गीत क्या है, लेकिन वह बिजोय इमैनुएल (1986) के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर किसी विवेक सम्मत आपत्ति दर्ज करने वाले (Conscientious Objector) नागरिक के मौन रहने को "बाधा या अपराध" मानकर दंडित नहीं कर सकती।

Q4. 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र और समकालीन वैश्विक कूटनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र की अध्यक्षता के लिए दक्षिण एशिया से बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को निर्वाचित किया गया है।
2. सुपरपावर देशों के आधिपत्य से परे जाकर बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ (EU) और कुछ अन्य देशों द्वारा शुरू की गई 'पार्टनरशिप फॉर मल्टीलेटरलिज्म' (P4M) पहल का भारत एक सह-प्रायोजक है।
3. भारत ने वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में वर्ष 2028-29 के लिए एक स्थायी सदस्य के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अभियान शुरू किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (A) केवल 1 और 2

व्याख्या :

- **कथन 1 सही है:** संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का यह 81वां सत्र दक्षिण एशिया के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को इसके 81वें सत्र के अध्यक्ष (President) के रूप में चुना गया है। वह अगले संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) के चयन की प्रक्रिया की देखरेख भी करेंगे।
- **कथन 2 सही है:** वैश्विक महाशक्तियों के आधिपत्य और ध्रुवीकरण से अलग हटकर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ (EU) और कुछ अन्य देशों के नेतृत्व में 'पार्टनरशिप फॉर मल्टीलेटरलिज्म' (Partnership for Multilateralism - P4M) नामक एक अच्छी पहल शुरू की गई है, जिसे भारत द्वारा सह-प्रायोजित (Co-sponsored) किया गया है। हालांकि, इस सत्र में वैश्विक तनावों के कारण इसकी गूंज कम रही।
- **कथन 3 गलत है:** भारत सरकार ने वर्ष 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में गैर-स्थायी सदस्य (Non-permanent Member) के रूप में अपने दूसरे दो वर्षीय कार्यकाल के लिए अभियान शुरू किया है, न कि स्थायी सदस्यता के कार्यकाल के लिए (स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा दीर्घकालिक और अलग है)। अतः यह कथन गलत हो जाता है।

Q5. अमेरिका द्वारा हाल ही में पारित 'लिंडसे ओ. ग्राहम सेंकशनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट (SRIA)' और भारत के हितों पर इसके प्रभाव।

साक्ष्य:

- I. अधिनियम अमेरिकी कार्यपालिका को रूसी तेल के शीर्ष पांच खरीदार देशों पर 100% तक दंडात्मक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है।
- II. वर्तमान में भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कुल कच्चे तेल में रूसी यूराल क्रूड की हिस्सेदारी लगभग 51% है।
- III. इस नए प्रतिबंधात्मक कानून (SRIA) की मूल भाषा में यह प्रावधान शामिल है कि अमेरिकी राष्ट्रीय हित में इन प्रतिबंधों को निलंबित किया जा सकता है।

निष्कर्ष :

1. साक्ष्य I और II यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नया अमेरिकी कानून भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के लिए एक गंभीर रणनीतिक चुनौती पैदा करता है।
2. साक्ष्य III यह निष्कर्ष निकालता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति घरेलू ईंधन की कीमतों और आगामी मध्यावधि चुनावों के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए भारत पर तुरंत पूर्ण दंडात्मक टैरिफ लगाने से बच सकते हैं।

उपर्युक्त साक्ष्यों और निष्कर्षों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

- (A) केवल निष्कर्ष 1, साक्ष्यों के आधार पर तार्किक रूप से सही है।
- (B) केवल निष्कर्ष 2, साक्ष्यों के आधार पर तार्किक रूप से सही है।
- (C) निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों, अपने संबंधित साक्ष्यों के आधार पर तार्किक रूप से सही हैं।
- (D) न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, साक्ष्यों के आधार पर सही निकाला गया है।

उत्तर: (C) निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों तार्किक रूप से सही हैं

व्याख्या:

- **निष्कर्ष 1 का विश्लेषण (सही):** साक्ष्य I और II के कड़ियों को जोड़ने पर यह निष्कर्ष बिल्कुल सटीक बैठता है। चूंकि भारत का 51% कच्चा तेल आयात रूसी यूराल क्रूड पर निर्भर है (साक्ष्य II) और अमेरिका उसी तेल के शीर्ष खरीदारों पर 100% टैरिफ लगाने का कानून लाया है (साक्ष्य I), तो यह स्वाभाविक रूप से भारत की घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डालता है और भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में एक बड़ा गतिरोध पैदा करता है।
- **निष्कर्ष 2 का विश्लेषण (सही):** साक्ष्य III के आधार पर निकाला गया यह निष्कर्ष भी तार्किक रूप से सही है। यद्यपि कानून सख्त है, लेकिन 'राष्ट्रीय हित में निलंबन' (National Interest Waiver) का प्रावधान होने के कारण अमेरिकी प्रशासन के पास लचीलापन है। अमेरिकी राष्ट्रपति घरेलू स्तर पर पेट्रोल (गैस) की कीमतों को स्थिर रखने और चुनाव (Midterm Elections) के समय वैश्विक तेल बाजार में बड़ा झटका न लगे, इसलिए इस छूट का उपयोग कर भारत पर तुरंत कठोर कार्रवाई करने से बच सकते हैं।

चूंकि दोनों निष्कर्ष अपने दिए गए साक्ष्यों के आधार पर पूरी तरह वैध (Logically Deducted) हैं, इसलिए विकल्प (C) सही उत्तर है।

Q6. भारत के परमाणु सिद्धांत (2003) के बुनियादी ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कारगिल युद्ध (1999) ने यह साबित किया कि परमाणु प्रतिरोध की उपस्थिति में भी दो देशों के बीच पारंपरिक युद्ध की संभावना बनी रहती है।
2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हाइपरसोनिक हथियारों और साइबर क्षमताओं जैसी विघटनकारी तकनीकों ने कमांड-एंड-कंट्रोल नेटवर्क की संवेदनशीलता को बढ़ाकर निर्णय लेने की समय-सीमा को छोटा कर दिया है।
3. भारत को अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को मजबूत करने के लिए वर्तमान 'नो फर्स्ट यूज़' नीति को पूरी तरह से त्यागकर 'पहले आघात' की घोषित नीति अपनानी चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (A) केवल एक कथन
- (B) केवल दो कथन
- (C) सभी तीनों कथन
- (D) कोई भी कथन सही नहीं है

उत्तर: (B) केवल दो कथन (कथन 1 और कथन 2 सही हैं)

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** 1998 के पोखरण-II परीक्षणों के ठीक बाद 1999 में हुआ कारगिल युद्ध यह दर्शाता है कि परमाणु हथियारों की मौजूदगी के बावजूद सीमित या पारंपरिक युद्ध पूरी तरह खारिज नहीं होता।
- **कथन 2 सही है:** आधुनिक विघटनकारी तकनीकें (Disruptive Technologies) परमाणु प्रतिरोध की स्थापित प्रणालियों को और अधिक असुरक्षित और त्वरित (Short Timeline) बना देती हैं, जिससे दूसरा आघात (Second Strike) सुनिश्चित करने में कठिनाई आती है।
- **कथन 3 गलत है:** 'नो फर्स्ट यूज' (NFU) नीति को छोड़ने की सलाह नहीं देता है। इसके विपरीत, लेख का कहना है कि स्थापित सिद्धांतों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या बदलाव से विरोधियों में अनिश्चितता पैदा होगी और संकट प्रबंधन (Crisis Management) जटिल हो जाएगा। प्राथमिकता नीति बदलने की नहीं, बल्कि क्षमताओं को मजबूत करने की होनी चाहिए।

Q7. यूपीआई (UPI) पर 15 अक्टूबर से लागू होने वाले 'मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट' (MDR) के आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एमडीआर (MDR) वह शुल्क है जिसे भुगतान प्रोसेसर और बैंक डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के बदले मर्चेन्ट (व्यापारी) से वसूलते हैं।
2. सरकार और भारतीय बैंक संघ (IBA) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मर्चेन्ट इस नए एमडीआर शुल्क का पूरा भार सीधे ग्राहकों पर स्थानांतरित न कर सकें।
3. पेट्रोलियम डीलरों और एसोसिएशनों ने इस एमडीआर शुल्क का स्वागत किया है क्योंकि इससे उनके शुद्ध लाभ मार्जिन (Profit Margins) में बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (A) केवल एक कथन
- (B) केवल दो कथन
- (C) सभी तीनों कथन
- (D) कोई भी कथन सही नहीं है

उत्तर: (B) केवल दो कथन (कथन 1 और कथन 2 सही हैं)

व्याख्या (Detailed Explanation of Statements):

- **कथन 1 सही है:** मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR) मूल रूप से वह सेवा शुल्क या दर है जो बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता (Payment Processors) किसी व्यापारी (Merchant) से डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे और सेवाएं प्रदान करने के बदले वसूलते हैं। यूपीआई (UPI) को एक वित्तीय सेवा माना जाता है, इसलिए इस पर एमडीआर लागू किया जा रहा है।
- **कथन 2 सही है:** सरकार और भारतीय बैंक संघ (IBA) के बीच चल रही वार्ताओं का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसी विनियामक और व्यावहारिक प्रणालियाँ बनाई जाएं जिससे व्यापारी इस एमडीआर शुल्क का बोझ सीधे आम ग्राहकों (Consumers) पर स्थानांतरित (Pass on) न कर सकें। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि डिजिटल लेनदेन के प्रति जनता का आकर्षण कम न हो।
- **कथन 3 गलत है:** पेट्रोलियम डीलरों और उनके संघों (Associations) ने इस एमडीआर शुल्क का स्वागत बिल्कुल नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इस शुल्क पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे पूरी तरह माफ (Waiver) करने की मांग की है। उनका तर्क है कि एमडीआर लागू होने से उनके शुद्ध लाभ मार्जिन (Profit Margins) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वह कम हो जाएगा, न कि उसमें वृद्धि होगी। इसी कारण पेट्रोलियम मंत्रालय इस मार्जिन राशि की समीक्षा के लिए डीलरों के साथ बातचीत कर रहा है।

चूंकि कथन 1 और कथन 2 पूरी तरह सही हैं और कथन 3 गलत है, इसलिए कुल दो कथन सही होने के कारण विकल्प (B) इस प्रश्न का सटीक उत्तर है।

Q8. हाल ही में समाचारों में रहे पूर्वोत्तर भारत के भूगोल और आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कामजोंग (Kamjong) जिला, जो हाल ही में सीमा पार से हुई उग्रवादी गतिविधियों के कारण चर्चा में रहा, भारत के नागालैंड राज्य में स्थित है।
2. तंगखुल नागा लोंग सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले तंगखुल नागा समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च सामाजिक-सांस्कृतिक और पारंपरिक संस्था है।
3. तंगखुल संस्था के कार्यसमिति के अनुसार, इस सीमा पार हमले को म्यांमार स्थित 'कुकी नेशनल आर्मी-बर्मा' और 'पीपुल्स डिफेंस फोर्स' के तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (A) केवल एक कथन
- (B) केवल दो कथन
- (C) सभी तीनों कथन
- (D) कोई भी कथन सही नहीं है

उत्तर: (B) केवल दो कथन (कथन 2 और कथन 3 सही हैं)

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है:** कामजोंग (Kamjong) जिला भारत के नागालैंड राज्य में नहीं, बल्कि मणिपुर राज्य में स्थित है। यह जिला म्यांमार के साथ एक लंबी और संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जहाँ हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ की हिंसक घटना हुई है।
- **कथन 2 सही है:** तंगखुल नागा लोंग (TNL) इस क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले तंगखुल नागा समुदाय की सर्वोच्च सामाजिक-सांस्कृतिक, पारंपरिक और प्रतिनिधि नागरिक संस्था (Apex Body) है।
- **कथन 3 सही है:** तंगखुल संस्था के कार्यसमिति (WC-TNL) के आधिकारिक बयान के अनुसार, इस हिंसक सीमा पार हमले को म्यांमार में सक्रिय 'कुकी नेशनल आर्मी-बर्मा' (KNA-B) और म्यांमार के ही सैन्य शासन विरोधी संगठन 'पीपुल्स डिफेंस फोर्स' (PDF) समर्थित तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय नदी सीमा पार कर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया।

चूंकि केवल दो कथन (कथन 2 और कथन 3) पूरी तरह सही हैं, इसलिए विकल्प (B) इस प्रश्न का सटीक उत्तर है।

Value Addition for Prelims:

- 1. नाम्या (Namya) नदी:** 'नाम्या नदी' भारत (मणिपुर का कामजोंग जिला) और म्यांमार (फाइलेन कुकी गाँव) के बीच एक महत्वपूर्ण भौगोलिक सीमा रेखा या नदीय मार्ग का निर्माण करती है, जिसका उपयोग उग्रवादियों द्वारा घुसपैठ के लिए किया गया।
- 2. फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) का संदर्भ:** भारत-म्यांमार सीमा पर हाल के वर्षों में बढ़ती अस्थिरता, अवैध घुसपैठ और उग्रवाद के कारण भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक 'फ्री मूवमेंट रिजीम' (FMR - जिसके तहत सीमा के दोनों ओर के लोग बिना वीजा के 16 किमी तक आ-जा सकते थे) को निलंबित करने और पूरी सीमा पर बाड़ लगाने (Fencing) का नीतिगत निर्णय लिया है।
- 3. असम राइफल्स (Assam Rifles):** भारत-म्यांमार की इस 1,643 किलोमीटर लंबी पहाड़ी और घने जंगलों वाली सीमा की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी असम राइफल्स के पास है, जिसे भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल भी कहा जाता है।

Q9. नागालैंड में AFSPA के हालिया भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नागालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा और मों (Mon) सहित कुल नौ जिलों को धारा 3 के तहत "अशांत क्षेत्र" घोषित कर इस कानून का विस्तार किया गया है.
2. कोहिमा और मोकोकचुंग जैसे जिलों में पूरे जिले के बजाय केवल कुछ विशिष्ट पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में ही इसे विस्तारित किया गया है.

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

व्याख्या :

- **कथन 1 सही है:** भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नागालैंड के कुल नौ जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) की धारा 3 के तहत पूरी तरह से "अशांत क्षेत्र" (Disturbed Area) घोषित किया गया है। इन नौ जिलों में दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक, पेरेन और मेलुरी शामिल हैं। अतः पहला कथन पूरी तरह सत्य है।
- **कथन 2 सही है:** अधिसूचना यह भी स्पष्ट करती है कि नागालैंड के कुछ अन्य जिलों को पूरी तरह अशांत घोषित करने के बजाय केवल आंशिक रूप से कवर किया गया है। कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेन्ग, वोखा और जुन्हेबोटो जैसे पांच जिलों में यह कानून पूरे जिले में लागू नहीं है, बल्कि केवल इनके 21 विशिष्ट पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में आने वाले क्षेत्रों में ही विस्तारित किया गया है। अतः दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है।

Q10. हाल ही में जारी आरबीआई (RBI) के बुलेटिन और भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक आर्थिक (Macroeconomic) स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में संप्रभु बांड प्रतिफल (Sovereign Yields) में हुई वृद्धि के कारण भारत सरकार के वित्त (Government Finances) पर दबाव देखा गया है।
2. पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने के बावजूद, अगस्त 2026 में हेडलाइन सीपीआई (CPI) मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति दोनों में भारी गिरावट दर्ज की गई।
3. अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए विशेष जमा योजना और FCNR(B) प्रवाह के कारण 18 सितंबर, 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार \$766 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।
4. वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार भारत के 11.2 महीने के वस्तु आयात और कुल बाहरी ऋण के 100% से अधिक को कवर करने में सक्षम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- | | |
|--------------------|-----------------|
| (A) केवल 1 और 2 | (B) केवल 2 और 4 |
| (C) केवल 1, 3 और 4 | (D) उपरोक्त सभी |

उत्तर: (C) केवल 1, 3 और 4

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** आरबीआई बुलेटिन के अनुसार, कुछ प्रमुख उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सॉवरेन बॉन्ड यील्ड (Sovereign Yields) बढ़ने से वैश्विक वित्तीय वातावरण चुनौतीपूर्ण हुआ है, जिसने भारत सरकार के वित्त (Government Finances) पर भी दबाव डाला है।
- **कथन 2 गलत है:** अगस्त 2026 में हेडलाइन सीपीआई (CPI) मुद्रास्फीति कम नहीं हुई, बल्कि इसमें बढ़ोतरी (Picked up) देखी गई है। साथ ही कीमती धातुओं को छोड़कर कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation) भी हाल के महीनों के अति-निम्न स्तर से ऊपर बढ़ी है। पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें मुद्रास्फीति के दबाव को और बढ़ा रही हैं।
- **कथन 3 सही है:** अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए शुरू की गई 'विशेष जमा योजना' और FCNR(B) खातों में आने वाले विदेशी निवेश के कारण 18 सितंबर, 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार \$766 बिलियन के ऐतिहासिक और रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
- **कथन 4 सही है:** बुलेटिन के अनुसार, \$766 बिलियन का यह विशाल विदेशी मुद्रा भंडार भारत को एक मजबूत बाहरी सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यह भंडार 18 सितंबर की स्थिति के अनुसार 11.2 महीने के वस्तु आयात (Goods Imports) के खर्च और मार्च 2026 के अंत तक भारत के कुल बकाया बाहरी ऋण (External Debt Outstanding) के 100% से अधिक का भुगतान करने में सक्षम है।

Value Addition for UPSC:

- **तरलता और ऋण चक्र (System Liquidity):** FCNR(B) प्रवाह में वृद्धि होने से भारतीय बैंकिंग प्रणाली में नकदी या तरलता (Liquidity) बढ़ी है। इसके कारण बैंकों में जमा राशि बढ़ने की रफ्तार तेज हुई है, जो अंततः देश में चल रहे ऋण वृद्धि चक्र (Credit Growth Cycle) को मजबूत सहारा दे रही है।
- **डाउनसाइड रिस्क (Downside Risks):** आरबीआई के अनुसार, भारत का वित्तीय और बाहरी क्षेत्र मजबूत बना हुआ है, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव (जैसे पश्चिम एशिया युद्ध) और मौसम संबंधी अनिश्चितताएं (Weather-related uncertainties) भारतीय आर्थिक विकास के मार्ग में प्रमुख नकारात्मक जोखिम (Downside Risks) के रूप में काम कर रही हैं।

Q11. नागोया (Nagoya) में आयोजित हालिया एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मनप्रीत कौर ने एशियाई खेलों की शॉट पुट (गोला फेंक) स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता।
2. गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया।
3. बारानिका एलांगोवन ने एशियाई खेलों की महिला पोल वॉल्ट (बांस कूद) स्पर्धा में ऐतिहासिक कांस्य पदक अपने नाम किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (D) 1, 2 और 3 (तीनों कथन बिल्कुल सही हैं)

व्याख्या :

- **कथन 1 सही है:** प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और पीआईबी दिल्ली द्वारा 25 सितंबर 2026 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनप्रीत कौर को एशियाई खेलों की शॉट पुट (गोला फेंक) स्पर्धा में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उनके एक शानदार श्रो ने भारत को इस स्पर्धा में कांस्य पदक (Bronze Medal) दिलाया।
- **कथन 2 सही है:** भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में असाधारण प्रदर्शन करते हुए रजत पदक (Silver Medal) जीता। इससे पूर्व उन्होंने एशियाई खेलों के पोटियम पर कांस्य पदक भी जीता था, और अब उन्होंने रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है।
- **कथन 3 सही है:** प्रधानमंत्री ने महिला एथलेटिक्स क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि की सराहना की। भारतीय महिला एथलीट बारानिका एलांगोवन ने अपने पहले एशियाई खेलों में पदार्पण करते हुए महिला पोल वॉल्ट (Pole Vault) स्पर्धा में देश के लिए कांस्य पदक (Bronze Medal) अर्जित किया। प्रधानमंत्री ने इसे भारत के लिए "एक विशेष पल और अनुकरणीय पदक" बताया जो कई और युवा खिलाड़ियों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

Q12. हाल ही में चर्चा में रहे 'क्वाड-एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन' (Quad-at-Sea Ship Observer Mission) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस ऐतिहासिक मिशन के संचालन के लिए भारतीय नौसेना के परमाणु-संपन्न युद्धपोत का उपयोग किया जा रहा है।
2. इस समुद्री मिशन में शामिल 'सी राइडर्स' अधिकारियों के दल में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी शामिल हैं।
3. 'शौनक' जहाज की इस यात्रा का अंतिम गंतव्य स्थल (Destination) जापान का टोक्यो बंदरगाह निर्धारित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- (A) केवल एक कथन
- (B) केवल दो कथन
- (C) सभी तीनों कथन
- (D) कोई भी कथन सही नहीं है

उत्तर: (A) केवल एक कथन (केवल कथन 2 सही है)

व्याख्या :

- **कथन 1 गलत है:** इस मिशन के संचालन के लिए भारतीय नौसेना (Indian Navy) के किसी परमाणु-संपन्न युद्धपोत का उपयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard - ICG) के जहाज 'शौनक' को तैनात किया गया है भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र और गैर-सैन्य तटीय सुरक्षा बल है।
- **कथन 2 सही है:** इस समुद्री मिशन में शामिल 'सी राइडर्स' (Sea Riders) अधिकारियों के दल में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी शामिल हैं। इन चारों देशों के गठबंधन को ही 'क्वाड' (Quad) समूह कहा जाता है। इस दल में भारत और जापान से दो-दो तथा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से एक-एक अधिकारी शामिल हुए हैं।
- **कथन 3 गलत है:** भारतीय तटरक्षक बल का जहाज 'शौनक' 25 सितंबर, 2026 को चेन्नई से खाना हुआ है और इस यात्रा का अंतिम गंतव्य स्थल (Destination) ऑस्ट्रेलिया का पर्थ (Perth) बंदरगाह निर्धारित किया गया है, न कि जापान का टोक्यो।

Q13. भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. निर्वाचन आयोग के सभी निर्णय अनिवार्य रूप से सर्वसम्मत होने चाहिए।
2. मतभेद होने की स्थिति में, मामले का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है।
3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
4. अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) को राष्ट्रपति द्वारा केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (B)

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है:** यह अनिवार्य नहीं है कि निर्वाचन आयोग के सभी निर्णय सर्वसम्मत (एकमत) ही हों। निर्वाचन आयोग (कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिशनर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस) एक्ट के तहत, यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) के बीच किसी मामले पर वैचारिक मतभेद होता है, तो उस मामले का निपटारा बहुमत (Majority Opinion) के आधार पर किया जाता है। आयोग में वर्तमान में तीन सदस्य (1 CEC और 2 ECs) होते हैं, इसलिए 2:1 के बहुमत से निर्णय लिया जा सकता है।
- **कथन 3 सही है:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) को पद की सुरक्षा प्राप्त है। उन्हें उनके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश (Judge of the Supreme Court) को हटाया जाता है। अर्थात्, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित दुर्व्यवहार या अक्षमता के प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है।
- **कथन 4 सही है:** संविधान के अनुच्छेद 324(5) के परंतुक (Proviso) में यह भी प्रावधान है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों (Election Commissioners) या क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। अर्थात्, उन्हें पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश की आवश्यकता होती है।

चूंकि कथन 2, 3 और 4 सही हैं, इसलिए विकल्प (b) सही उत्तर है।

Q14. भारत के विभिन्न देशों और वैश्विक गुटों के साथ हालिया द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को दिसंबर 2026 में हस्ताक्षरित किया जाना निर्धारित है, जिसे यूरोपीय परिषद की स्वीकृति के बाद प्रत्येक ईयू सदस्य देश द्वारा अलग से अनुमोदित (Ratify) करना अनिवार्य होगा।
2. भारत और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को दिसंबर 2026 में जी20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) के दौरान अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।
3. भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) में देरी का एक प्रमुख कारण भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर अमेरिका द्वारा लगाया जाने वाला संभावित टैरिफ का खतरा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 3
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: (C)

व्याख्या:

- कथन 1 गलत है:** भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (India-EU FTA) को यूरोप में "बहुमत की मंजूरी" मिल चुकी है। यूरोपीय परिषद (European Council) से मंजूरी मिलने के बाद, इसे प्रत्येक ईयू देश द्वारा अलग से अनुसमर्थन या अनुमोदित (Separate Ratification) करने की आवश्यकता नहीं होगी। यूरोपीय संसद द्वारा आगामी एक से दो महीनों में इसे पारित करने की उम्मीद है, जिससे इसे शुरुआती 2027 में लागू किया जा सके।
- कथन 2 सही है:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2026 में कनाडा का दौरा कर सकते हैं, जहाँ भारत-कनाडा मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। दोनों देशों का लक्ष्य अमेरिका में आयोजित होने वाले दिसंबर जी20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) तक इन वार्ताओं को सफलतापूर्वक संपन्न करना है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी इस व्यापारिक रिश्ते की प्रगति को महत्वपूर्ण बताया है।
- कथन 3 सही है:** भारत और अमेरिका के बीच व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) और अंतरिम समझौते में लगातार देरी हो रही है। इसका एक बड़ा कारण अमेरिकी कार्यपालिका द्वारा भारत पर लगाए जा रहे पारस्परिक टैरिफ (Reciprocal Tariffs) तो हैं ही, साथ ही भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात जारी रखने के कारण अमेरिका द्वारा लगाया जाने वाला संभावित 100% तक का टैरिफ खतरा भी दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव पैदा कर रहा है।

Q15. 11वें आयुर्वेद दिवस (2026) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष भगवान धन्वंतरि जयंती (धनतेरस) के अवसर पर मनाया जाता है।
2. इस वर्ष (2026) के आयुर्वेद दिवस की मुख्य विषय "स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद" रखी गई है।
3. आयुष मंत्रालय भारत में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी प्रणालियों के विकास के लिए नोडल मंत्रालय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (D) 1, 2 और 3

व्याख्या :

- **कथन 1 सही है:** भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2016 में प्रथम आयुर्वेद दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तब से इसे प्रतिवर्ष भगवान धन्वंतरि जयंती (धनतेरस) के पावन अवसर पर मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरि को भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद का जनक और स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। चूंकि धनतेरस की तिथि हिंदू चंद्र कैलेंडर (विक्रम संवत्) के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भी यह हर साल अलग-अलग तारीखों पर आता है।
- **कथन 2 सही है:** वर्ष 2026 में मनाए गए 11वें आयुर्वेद दिवस की आधिकारिक मुख्य विषय (Theme) "स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद" रखा गया है। यह विषयवस्तु आयुर्वेद को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों के साथ जोड़ने, निवारक स्वास्थ्य देखभाल (Preventive Healthcare) को बढ़ावा देने और आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों (Clinical Trials) के साथ प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को सिद्ध करने पर केंद्रित है।
- **कथन 3 सही है:** भारत में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को एक व्यवस्थित ढांचा देने के लिए 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) की स्थापना की गई थी। यह मंत्रालय भारत की पाँच पारंपरिक और गैर-एलोपैथिक प्रणालियों (A-आयुर्वेद, Y-योग और प्राकृतिक चिकित्सा, U-यूनानी, S-सिद्ध और H-होम्योपैथी) के नियमन, विकास और नीतियों के निर्माण के लिए सर्वोच्च नोडल संस्था है।

Q16. महिला किसानों और कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLPR) में हाल के वर्षों में गिरावट दर्ज की गई है।
2. पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना के तहत देश भर में महिला लाभार्थी कुल लाभार्थियों के 50% से अधिक हैं।
3. महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने भूमि स्वामित्व के बिना भी महिलाओं को 'महिला किसान प्रमाण पत्र' के माध्यम से स्वतंत्र किसान के रूप में मान्यता देने के लिए विधेयक पारित किया है।
4. केरल का 'कुडुम्बश्री' (Kudumbashree) कार्यक्रम महिलाओं को सामूहिक खेती के लिए संगठित कर उन्हें सशक्त बनाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-----------------|------------------|
| A. केवल एक कथन | B. केवल दो कथन |
| C. केवल तीन कथन | D. सभी चारों कथन |

उत्तर: (B) केवल दो कथन

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है:** भारत में वर्तमान में कृषि का नारीकरण (Feminization of Agriculture) देखा जा रहा है। ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLPR) में हाल के वर्षों में गिरावट दर्ज नहीं की गई है, बल्कि इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह दर वर्ष 2022-23 में 41.5% थी, जो बढ़कर वर्ष 2023-24 में 47.6% हो गई है।
- **कथन 2 गलत है:** भारत में अधिकांश सरकारी और प्रशासनिक डेटाबेस किसी व्यक्ति को किसान मानने के लिए भूमि राजस्व शीर्षक (Land Revenue Titles) यानी जमीन के मालिकाना हक को ही प्राथमिक आधार मानते हैं। चूंकि ग्रामीण भारत में महिलाओं के नाम पर जमीन बहुत कम है, इसलिए वे कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाती हैं। यही कारण है कि देश भर में पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या कुल लाभार्थियों की केवल 23% से 25% ही है, जो कि 50% से काफी कम है।

- **कथन 3 सही है:** महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 'महिला किसान अधिकार विधेयक' (Women Farmers' Empowerment Bill) पारित किया है। इस ऐतिहासिक कानून के तहत, भूमि का मालिकाना हक (स्वामित्व) महिला के नाम पर न होने के बावजूद, उसे 'महिला किसान प्रमाण पत्र' (Woman Farmer Certificate) जारी किया जाता है, जिससे उसे प्रशासनिक और सरकारी तौर पर एक स्वतंत्र किसान के रूप में पहचान और अधिकार मिलते हैं।
- **कथन 4 सही है:** केरल का 'कुडुम्बश्री' (Kudumbashree) मॉडल देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक खेती (Collective Farming) के समूहों में संगठित किया जाता है। ये महिलाएं पट्टे (Lease) पर जमीन लेती हैं, खेती करती हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं और इसके आधार पर उन्हें बैंकों से संस्थागत ऋण (Financial Credit) भी आसानी से प्राप्त हो जाता है।

Q17. कर्नाटक सरकार द्वारा तुलु भाषा को अतिरिक्त प्रशासनिक भाषा का दर्जा देना और इसके विधिक व भाषाई आयाम।

- I. कर्नाटक सरकार ने तुलु भाषा को राज्य की दूसरी अतिरिक्त प्रशासनिक भाषा का दर्जा दिया है, जो विशेष रूप से दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों पर लागू होगा।
- II. तुलु एक प्रमुख द्रविड़ भाषा है जिसे 'पंच-द्रविड़' भाषाओं में गिना जाता है और इसकी अपनी स्वदेशी लेखन प्रणाली है जिसे 'तुलु लिपि' या 'तिगलारी' कहा जाता है।
- III. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता देती है, परंतु निरंतर मांगों के बावजूद तुलु भाषा अभी भी इसमें शामिल नहीं है।

निष्कर्ष:

1. साक्ष्य I और II यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कर्नाटक सरकार का यह निर्णय किसी भाषाई समुदाय की समृद्ध साहित्यिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत (जैसे यक्षगान और भूता कोला) को प्रशासनिक संरक्षण प्रदान करने तथा क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने का एक व्यावहारिक प्रयास है।
2. साक्ष्य III यह निष्कर्ष निकालता है कि किसी भाषा को राज्य स्तर पर आधिकारिक या प्रशासनिक दर्जा प्राप्त होने का अर्थ यह अनिवार्य रूप से नहीं है कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक मान्यता (आठवीं अनुसूची के तहत) भी प्राप्त हो चुकी हो।

उपर्युक्त साक्ष्यों और निष्कर्षों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

- (A) केवल निष्कर्ष 1, साक्ष्यों के आधार पर तार्किक रूप से सही है।
- (B) केवल निष्कर्ष 2, साक्ष्यों के आधार पर तार्किक रूप से सही है।
- (C) निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों, अपने संबंधित साक्ष्यों के आधार पर तार्किक रूप से सही हैं।
- (D) न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, साक्ष्यों के आधार पर सही निकाला गया है।

उत्तर: (C) निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों तार्किक रूप से सही हैं

व्याख्या:

- **निष्कर्ष 1 सही है:** तुलु भाषा पंच-द्रविड़ परिवार का हिस्सा है और इसकी अपनी अनूठी तिगलारी लिपि व समृद्ध लोक परंपराएं हैं। इसे तटीय जिलों में प्रशासनिक दर्जा देना इस क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत को विधिक रूप से संरक्षित करने की पुष्टि करता है।
- **निष्कर्ष 2 सही है:** कर्नाटक में इसे प्रशासनिक भाषा का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह अभी भी भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची से बाहर है, जो इन दोनों विधिक दर्जों के बीच के अंतर को साबित करता है।

Q18. भारतीय विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र और 'मेक इन इंडिया' (Make in India) अभियान के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत के बाद से वैश्विक वस्तु निर्यात (Global Goods Exports) में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1.7% पर स्थिर रही है।
2. विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित (GVA) की हिस्सेदारी वर्ष 2025-26 में बढ़कर 15.6% हुई है, जो कि 2014 में अभियान की शुरुआत के समय के स्तर से भी अधिक है।
3. निजी क्षेत्र द्वारा वास्तविक परिसंपत्तियों पर किए जाने वाले खर्च का पैमाना यानी सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF), जीडीपी (GDP) के प्रतिशत के रूप में हाल के वर्षों (2022-23 से) में लगातार गिर रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3 (उपरोक्त सभी)

उत्तर: (C) केवल 1 और 3

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** समाचार पत्र के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत के बाद से वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी में कोई बड़ी संरचनात्मक वृद्धि नहीं हुई है और यह 1.7% के स्तर पर आकर स्थिर (Flattened) हो गई है।
- **कथन 2 गलत है:** विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित (GVA) की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 के 14.6% से आंशिक रूप से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 15.6% जरूर हुई है [इमेज]। लेकिन लेख स्पष्ट करता है कि यह हिस्सेदारी वर्ष 2014 में 'मेक इन इंडिया' अभियान की शुरुआत के समय के स्तर से अभी भी कम है।
- **कथन 3 सही है:** अर्थव्यवस्था में निजी निवेश के मुख्य संकेतक यानी सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation - GFCF) की स्थिति चिंताजनक है [इमेज]। यह पैमाना (निजी क्षेत्र द्वारा नई मशीनरी और कारखानों पर होने वाला वास्तविक खर्च) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2022-23 के बाद से लगातार नीचे गिर रहा है।

Q19. हाल ही में घोषित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

क्रम	राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी	विजेता फिल्म / व्यक्ति
1.	सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म	आर्टिकल 370 (हिंदी)
2.	निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म	स्वातंत्र्य वीर सावरकर (रणदीप हुड्डा)
3.	मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता	ममूटी और कार्तिक आर्यन (संयुक्त रूप से)
4.	सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म	राम-नामी (हिंदी)

उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- A. केवल एक युग्म
- B. केवल दो युग्म
- C. केवल तीन युग्म
- D. सभी चारों युग्म

उत्तर: (3) केवल तीन कथन

व्याख्या:

- **युग्म 1 सही सुमेलित है:** वर्ष की 'सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म' का गौरव हिंदी फिल्म 'आर्टिकल 370' को मिला है, जिसके निर्माता जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज तथा निर्देशक आदित्य सुहास जंभाले हैं।
- **युग्म 2 सही सुमेलित है:** 'निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म' (Best Debut Film of a Director) की श्रेणी में हिंदी फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए रणदीप हुड्डा को विजेता घोषित किया गया है।
- **युग्म 3 सही सुमेलित है:** 'मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का पुरस्कार संयुक्त रूप से (Jointly) दो अभिनेताओं को मिला है—ममूटी (फिल्म: भ्रमायुगम, मलयालम) और कार्तिक आर्यन (फिल्म: चंदू चैंपियन, हिंदी)।
- **युग्म 4 गलत सुमेलित है:** 'सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म' (Best Non-Feature Film) का पुरस्कार 'भंगार' (मराठी और अंग्रेजी) को मिला है, जिसकी निर्माता और निर्देशिका सुमिरा रॉय हैं। जबकि 'राम-नामी' (हिंदी) को 'सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र' (Best Documentary) की श्रेणी में पुरस्कार मिला है, जिसके निर्देशक भारतबाला गणपति हैं।

Q20. हाल ही में संपन्न हुए भारत-श्रीलंका वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'स्लिनेक्स-26' (SLINEX-26) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस वर्ष विशाखापत्तनम में 'स्लिनेक्स-26' के 15वें संस्करण का सफल आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत समुद्री चरण से होकर बंदरगाह चरण पर समाप्त हुई।
2. इस समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत आईएनएस कवरत्ती और टैंकर जहाज आईएनएस ज्योति ने भाग लिया है।
3. वर्ष 2005 में शुरू हुआ 'स्लिनेक्स' अभ्यास भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान (Western Naval Command) की रणनीतिक देखरेख में आयोजित किया जाता है।
4. श्रीलंका की नौसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में एसएलएनएस सिंदुराला (SLNS Sindurala) पोत शामिल हुआ है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-----------------|------------------|
| A. केवल एक कथन | B. केवल दो कथन |
| C. केवल तीन कथन | D. सभी चारों कथन |

उत्तर: (B) केवल दो कथन

व्याख्या :

- **कथन 1 गलत है:** विशाखापत्तनम में आयोजित भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच का यह 13वां संस्करण था, न कि 15वां। इसके अलावा, इस युद्धाभ्यास की शुरुआत बंदरगाह चरण (Harbour Phase) से हुई थी, जिसके बाद इसका समुद्री चरण (Sea Phase) आयोजित किया गया और संपन्न हुआ। अतः पहला कथन गलत है।
- **कथन 2 सही है:** स्लिनेक्स-26 अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेशी एंटी-सबमरीन वारफेयर कार्वेट (पनडुब्बी रोधी युद्धपोत) आईएनएस कवरत्ती (INS Kavaratti) और फ्लीट टैंकर जहाज आईएनएस ज्योति (INS Jyoti) ने भाग लेकर अपनी परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
- **कथन 3 गलत है:** भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस युद्धाभ्यास की परिकल्पना वर्ष 2005 में की गई थी। हालांकि, विशाखापत्तनम में आयोजित यह संस्करण भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान (Eastern Naval Command) की रणनीतिक देखरेख और तत्वावधान में आयोजित किया गया था, न कि पश्चिमी नौसेना कमान की देखरेख में।
- **कथन 4 सही है:** द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास में श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्व करने और उनकी परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए उनका प्रसिद्ध अपतटीय गश्ती पोत (Offshore Patrol Vessel) एसएलएनएस सिंदुराला (SLNS Sindurala) शामिल हुआ था।

Q21. भारत में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision - SIR) और विधिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं की मतदाता सूचियां तैयार करने के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है।
2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RPA, 1950) की धारा 22 चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ERO) को मतदाता सूची में अपात्र, मृत या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम को संशोधित या विलोपित करने का वैधानिक अधिकार देती है।
3. निर्वाचन आयोग किसी मृत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए केवल सॉफ्टवेयर जनित डेटा पर निर्भर कर सकता है और इसके लिए परिवार के सदस्यों को कोई पूर्व नोटिस जारी करना अनिवार्य नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| (A) केवल 1 और 2 | (B) केवल 2 और 3 |
| (C) केवल 1 और 3 | (D) 1, 2 और 3 (उपरोक्त सभी) |

उत्तर: (A) केवल 1 और 2

व्याख्या :

- **कथन 1 सही है:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संसद, राज्य विधानमंडलों, तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची (Electoral Rolls) तैयार करने का पूर्ण अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है।
- **कथन 2 सही है:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 22 के तहत संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी पंजीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer - ERO) को यह वैधानिक शक्ति प्राप्त है कि यदि कोई व्यक्ति अपात्र पाया जाता है, या उसका नाम किसी अन्य स्थान पर पंजीकृत हो गया है, या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो वह मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन, प्रविष्टि को वापस या विलोपित (Delete) कर सकता है।
- **कथन 3 गलत है:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice) और निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, किसी भी मतदाता का नाम सूची से हटाने या उसकी पात्रता पर सवाल उठाने से पहले सत्यापन नोटिस जारी करना और सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य होता है। यदि कोई तकनीकी विसंगति (जैसे सॉफ्टवेयर द्वारा नो-मैपिंग या नाम बेमेल फ्लैग करना) पाई जाती है, या कोई व्यक्ति मृत पाया जाता है, तब भी विधिक प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए नोटिस जनरेट किया जाता है ताकि किसी वैध नागरिक का मताधिकार न छीने। आयोग केवल सॉफ्टवेयर के निष्कर्षों पर सीधे नाम नहीं हटा सकता।

Q22. भारत के विस्तारित सेमीकंडक्टर विजन और 'सेमीकॉन 2.0' (Semicon 2.0) कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के नए सेमीकंडक्टर विजन का दायित्व केवल बुनियादी असेंबली और परीक्षण (ATMP) तक सीमित है, और इसमें चिप डिजाइन या फैब्रिकेशन शामिल नहीं है।
2. सरकार ने सेमीकंडक्टर कार्यक्रम के दूसरे चरण (Semicon 2.0) के तहत ₹1.27 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
3. इस अभियान के तहत ऑटोमोटिव (वाहनों), उपभोक्ता उपकरणों (जैसे टीवी, फ्रिज) और औद्योगिक पावर सिस्टम के लिए 'मैच्योर नोड' और एप्लीकेशन-विशिष्ट चिप्स का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है।
4. मानव संसाधन विकास के तहत, भारत ने शुरुआती प्रशिक्षण लक्ष्यों को पूरा करते हुए 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने की क्षमता विकसित की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| (A) केवल 1, 2 और 3 | (B) केवल 2, 3 और 4 |
| (C) केवल 1, 3 और 4 | (D) 1, 2, 3 और 4 (उपरोक्त सभी) |

उत्तर: (B) केवल 2, 3 और 4

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है:** गद्यांश के अनुसार, भारत अपने पुराने सीमित दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। नया विजन केवल बुनियादी असेंबली और परीक्षण (Basic Assembly and Testing) तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे को व्यापक (Broader Scope) बनाया गया है। इसमें अब चिप डिजाइन (Chip Design), फैब्रिकेशन (Fabrication), उपकरण (Equipment) और कच्चे माल (Raw Materials) के घरेलू उत्पादन को भी शामिल किया गया है।
- **कथन 2 सही है:** भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता की घोषणा की है। सेमीकंडक्टर कार्यक्रम के दूसरे चरण यानी सेमीकॉन 2.0 (Semicon 2.0) के तहत सरकार ने ₹1.27 लाख करोड़ के भारी-भरकम बजटीय फंड की प्रतिबद्धता जताई है।

- **कथन 3 सही है:** भारत का तात्कालिक रणनीतिक फोकस उच्च-स्तरीय आधुनिक चिप्स के बजाय दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए आवश्यक चिप्स पर है। इसके तहत ऑटोमोटिव (कार), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (टीवी, रेफ्रिजरेटर) और महत्वपूर्ण बिजली बुनियादी ढांचे (Industrial Power Systems) के लिए 'मैच्योर नोड' (Mature Node) और विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी चिप्स (Application-specific chips) की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **कथन 4 सही है:** सेमीकंडक्टर उद्योग में उच्च तकनीकी कौशल वाले कार्यबल की कमी को दूर करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) और प्रतिभा विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत ने इस क्षेत्र में अपने शुरुआती प्रशिक्षण लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हुए 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों का एक मजबूत कार्यबल (Talent Pool) तैयार करने की दिशा में बड़ी प्रगति की है।

Q23. सर्वोच्च न्यायालय के जसकरण जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य (2026) निर्णय और अनुच्छेद 22 के संवैधानिक सुरक्षा उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन के कारण किसी अभियुक्त को रिहा किया जाना तकनीकी रूप से 'जमानत मंजूर करना' माना जाता है, जो प्रारंभिक गिरफ्तारी को वैध रखते हुए पुलिस कस्टडी को समाप्त करता है।
2. मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) के निर्णय के अनुसार, अब सभी कानूनों के तहत गिरफ्तारी के लिखित आधार अभियुक्त को उसकी समझ आने वाली भाषा में प्रदान करना अनिवार्य है।
3. यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार न बताने के कारण रिहा किया जाता है, तो जांच एजेंसी मजिस्ट्रेट की अनुमति और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समर्थन के बिना उसे एकतरफा रूप से पुनः गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| (A) केवल एक कथन | (B) केवल दो कथन |
| (C) सभी तीनों कथन | (D) कोई भी कथन सही नहीं है |

उत्तर: (B) केवल दो कथन (कथन 2 और कथन 3 सही हैं)

व्याख्या:

- कथन 1 गलत है:** न्यायालय ने इस निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22(1) के तहत विधिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण अभियुक्त की रिहाई जमानत (Bail) का अनुदान नहीं है। यह वास्तव में एक "अवैध और असंवैधानिक हिरासत से मुक्ति" (Release from illegal and unconstitutional detention) है, जो कानूनी रूप से पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक गिरफ्तारी को ही पूरी तरह से शून्य और अमान्य (Null and Void) मानती है। अतः पहला कथन गलत हो जाता है।
- कथन 2 सही है:** गद्यांश के अनुसार, पंकज बंसल (2023) वाद (जो केवल पीएमएलए कानून तक सीमित था) के सिद्धांतों का विस्तार करते हुए मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) के ऐतिहासिक निर्णय में यह व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है कि सभी कानूनों (Across all statutes) के तहत गिरफ्तारी के लिखित आधार (Written Grounds) अभियुक्त को दिए जाने चाहिए, और वे उसी भाषा में होने चाहिए जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझता हो।
- कथन 3 सही है:** संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर एक बार रिहा होने के बाद, पुलिस या जांच एजेंसियों को दोबारा मनमानी या एकतरफा गिरफ्तारी करने से रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। अब एक नई गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट से स्पष्ट न्यायिक मंजूरी लेना अनिवार्य है, आवेदन को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा समर्थित होना चाहिए, जांच को किसी अन्य अधिकारी को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, और दोषी अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू होनी चाहिए।

Q24. हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के मानदंडों के आधार पर अपने राज्य में 100% सूखा घोषित करने की घोषणा की है तथा इसके तहत छात्रों की फीस माफी और बिजली बिलों में कटौती जैसे राहत उपाय शुरू किए हैं?

- (A) गुजरात सरकार**
- (B) मध्य प्रदेश सरकार**
- (C) कर्नाटक सरकार**
- (D) महाराष्ट्र सरकार**

उत्तर: (D) महाराष्ट्र सरकार

व्याख्या :

- हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने यह आधिकारिक बयान दिया है कि राज्य में मानसून की भारी कमी के कारण गंभीर शुष्क दौर (Dry Spell) देखा जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप सोयाबीन, कपास और गन्ने जैसी प्रमुख फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के नियमों और मानदंडों के तहत सितंबर के अंत तक पूरे राज्य में 100% सूखा घोषित करने की तैयारी कर रही है।
- **शुरू किए गए राहत उपाय:** संकट की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इसके तहत प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों के लिए स्कूल/कॉलेज शुल्क की माफी (Fee Waiver), ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिलों की माफी तथा गंभीर जल संकट से जूझ रहे गांवों में पीने के पानी के लिए सरकारी टैंकों की तैनाती जैसे कल्याणकारी उपाय शुरू किए गए हैं।

Q25. हाल ही में समाचारों में देखी गई 'तल्कायो' (Tilcayo / Leopardus tilcayo) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह बिल्ली परिवार की एक नई खोजी गई प्रजाति है, जो बोलीविया के हरे-भरे पर्वतीय 'युंगास' क्लाउड फॉरेस्ट (Yungas Cloud Forest) में पाई जाती है।
2. आनुवंशिक डेटा के विश्लेषण से यह पुष्टि हुई है कि यह बिल्ली लगभग 1.4 मिलियन वर्ष पहले अन्य टाइगर बिल्लियों के वंश से अलग हो गई थी।
3. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट के अनुसार, वर्तमान में टाइगर बिल्लियों (Tiger Cats) को 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' (Critically Endangered) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3 (उपरोक्त सभी)

उत्तर: (A) केवल 1 और 2

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** शोधकर्ताओं ने दक्षिण अमेरिका के बोलीविया देश के हरे-भरे 'युंगास' क्लाउड फॉरेस्ट (Lush Yungas Forest) में जंगली बिल्ली की एक नई जीवित प्रजाति की पहचान की है। स्थानीय समुदायों द्वारा इसे 'तल्कायो' (Tilcayo) कहा जाता है और शोधकर्ताओं ने इसे आधिकारिक तौर पर *Leopardus tilcayo* वैज्ञानिक नाम दिया है। यह एक सदी से भी अधिक समय में पहली बार है जब किसी नई जीवित बिल्ली प्रजाति का औपचारिक रूप से नामकरण और वर्णन किया गया है।
- **कथन 2 सही है:** दक्षिण अमेरिकी देशों से लिए गए बिल्लियों के डीएनए (DNA) नमूनों के आनुवंशिक विश्लेषण से यह प्रमाणित हुआ है कि टाइगर बिल्लियाँ वास्तव में पांच आनुवंशिक रूप से अलग प्रजातियाँ हैं। इस शोध से यह भी पता चला है कि तल्कायो (Tilcayo) का वंश लगभग 1.4 मिलियन वर्ष पहले अन्य टाइगर बिल्लियों से अलग (Separated) हो गया था, जो बिल्ली परिवार में एक नई प्रजाति-स्तरीय विभाजन को दर्शाता है।
- **कथन 3 गलत है:** अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट के अनुसार, घटती आबादी वाली इन टाइगर बिल्लियों की प्रजातियों को वर्तमान में 'संवेदनशील' (Vulnerable) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, न कि 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' (Critically Endangered) श्रेणी में। अतः तीसरा कथन गलत हो जाता है।

Thanks For Watching

Follow us for more Updates



@RRESULTMITRAOFFICIAL



Join our Telegram



@SUNILVERMA_THEIASMENTOR



Follow on Instagram



Subscribe Now

Stay Connected

Learn
Share
Grow
Together ♥

Better
Students
Brighter
Tomorrow

DISCIPLINE
CONSISTENCY
SUCCESS

Small
Steps
Big
Results
😊